दैनिक जागरण
जीवन की दशा बदलनी है तो पहले कर्म की दिशा बदलिए

आर्थिक भगोड़ों पर शिकंजा

आर्थिक रूप से बड़े देशों के समूह जी-20 के साझा घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया जाना भारत की एक बड़ी जीत है कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। भारत एक अर्से से यह मांग करता चला आ रहा है कि विश्व समुदाय भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे ऐसे अपराधी किसी भी देश में शरण न ले सकें। हालांकि आर्थिक अपराध को अंजाम देने के बाद अपने देश से निकल कर किसी अन्य देश में शरण लेने वालों से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी को पहली बार भारत ने ही प्रमुखता से बयान किया। यह अच्छा है कि जी-20 समूह ने भारत की इस पुरानी मांग को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया, लेकिन बेहतर यह होगा कि इस समस्या के समाधान के लिए वैसे ही कुछ नियम-कानून बनाए जाएं जैसे काला धन जमा करने वालों के खिलाफ बनने शुरू हुए हैं। यह ध्यान रहे कि इस तरह के नियम-कानून बनाने की जरूरत भी भारत ने ही रेखांकित की थी। आज जब विश्व अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है तब फिर यह भी समय की मांग है कि आर्थिक अपराध से निपटने में भी दुनिया के देश सहयोग का परिचय दें। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई आर्थिक अपराधी किसी अन्य देश जाकर वहां की नागरिकता लेने में समर्थ रहे। कारोबारी के रूप में किसी अन्य देश के बाशिंदे को नागरिकता देने के पहले यह जांच-परख की ही जानी चाहिए कि कहीं उसने अपने देश में कोई आर्थिक अपराध तो नहीं किया है?

समस्या केवल इतनी ही नहीं है किधोखाधड़ी करके भाग जाने वाले आसानी से अन्य देश की नागरिकता पाने में समर्थ हो जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे मानवाधिकारों की आड़ भी हासिल कर ले रहे हैं। कई देशों की कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में बरसों लग जाते हैं। यह एक तथ्य है कि ब्रिटेन से विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी हो रही है। इसी तरह की देरी मेहुल चोकसी के मामले में भी हो रही है, जिसने एंटीगुआ में शरण ले रखी है। भारत की तमाम कोशिश के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने उसकी नागरिकता रद करने की हामी तो भर दी है, लेकिन कहना कठिन है कि प्रत्यर्पण संबंधी कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? यह अजीब है कि एक ओर ब्रिटेन और एंटीगुआ जैसे देश हैं जो आर्थिक भगोड़ों को प्रत्यर्पित करने में जरूरत से ज्यादा समय लेते हैं और दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं जो गड़बड़ी के सुबूत देखते ही संदिग्ध व्यक्ति को उसके देश भेजने में तत्परता दिखाते हैं। जैसे काला धन छिपाने वालों पर कोई रहम नहीं किया जाना चाहिए वैसे ही आर्थिक भगोड़ों पर भी। जी-20 समूह को इसका अहसास होना चाहिए कि उसकी ओर से की जाने वाली घोषणाओं के अमल में जब देरी होती है तो उसकी सामर्थ्य को लेकर सवाल ही उठते हैं। इस समूह को अपनी घोषणाओं के अमल में कहीं अधिक तत्पर दिखना चाहिए।

कड़ी कार्रवाई की दरकार

झारखंड में डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने व हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम सिंहभूम के सोनुवा में डायन के नाम पर हिंसा की हृदयविदारक घटना सामने आई। अंधविश्वास की पराकाष्ठा पार कर चुके दो भाइयों ने डायन के संदेह में अधेड़ महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वहीं बीच-बचाव करने आई उसकी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। रामगढ़ के कौथा में ऐसा मामला सामने आया जिसमें पांचों आरोपी फरार हैं। दो वर्ष पूर्व रांची के मांडर में पांच महिलाओं को डायन बताकर गांव के तीन दर्जन से अधिक लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। सभ्य समाज में इस तरह की घटना कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सरकार ने लोगों को जागरूक करने लिए जनजागरूकता अभियान चलाने की बात कही थी। मांडर जैसी घटना के बाद अभियान चलाया गया, लेकिन धीरे-धीरे वह सुस्त पड़ गया। इस पर सतत अभियान चलाने की जरूरत है। इन सबके पीछे लोगों की अज्ञानता के साथ सबसे ज्यादा दोषी गांव के तांत्रिक व ओझा हैं जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को गुमराह कर हत्या व प्रताड़ना के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्हें बरगलाने वाले ओझा व तांत्रिक को भी तत्काल गिरफ्तारी हो। उन पर कठोर कार्रवाई के बाद ही इस पर लगाम लग सकता है। सरकार ने पूर्व में डायन से जुड़े मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाने की बात कही थी जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिले। ताजा मामले में कार्रवाई होने पर लोगों के जेहन में भी यह रहे कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा मिलती है। इन तमाम प्रयासों का तत्काल जमीनी स्तर पर असर नहीं दिख रहा है। सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जागरूकता अभियान क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। अगर यह सही तरीके से चलाया जाता तो इसका असर दिखता और डायन के नाम पर प्रताड़ना का सिलसिला थमता। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले पर गंभीर होगी और इस तरह के मामले पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति बनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी अन्यथा ऐसी घटनाओं पर विराम लगाना मुश्किल होगा।

अमेरिका से भारत की अपेक्षाएं

संजय गुप्त

भारत को अमेरिका से न केवल अपनी जरूरत के हिसाब से रक्षा तकनीक चाहिए, बल्कि वह तकनीक भी चाहिए जो देश में स्वास्थ्य, शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर सके

ओसाका में आयोजित जी-20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को निखारने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विभिन्न मसलों पर वार्ता के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह सहज दिखाई दिए उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को यह समझाने में सफल रहे कि भारत अपने हितों के साथ समझौता करने की स्थिति में नहीं। यह तो तय था कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ईरान, रक्षा समेत विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी, क्योंकि जापान रवाना होने के पहले ही ट्रंप यह कह चुके थे कि उन्हें अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का भारत का फैसला मंजूर नहीं, लेकिन ओसाका में उन्होंने जिस तरह भारत से संबंध मजबूत करने पर बल दिया और भारत से निकटता का हवाला देते हुए पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया उससे यही लगता है कि उन्हें यह आभास हुआ कि मोदी के नेतृत्व वाले भारत को दबाया नहीं जा सकता। भारत-अमेरिका के रिश्ते सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसका संकेत दोनों नेताओं के बीच बनी इस सहमति से मिला कि व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच जल्द ही बैठक होगी। उल्लेखनीय है कि दोनों नेताओं की वार्ता में रूसी मिसाइल सिस्टम एस-400 पर कोई चर्चा नहीं हुई। अमेरिका इस सौदे पर आपत्ति जता जा चुका है। ट्रंप प्रशासन चीनी कंपनी हुआवे के प्रति भी भारत को आगाह करते हुए यह चाह रहा है कि वह भी इस कंपनी के खिलाफ अमेरिका जैसा रुख क्यों नहीं अपना रहा है?

जी-20 की बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने के कारण विश्व आशंकित है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर न केवल जोर दे रहे हैं, बल्कि उसे बढ़ावा देते हुए वह विभिन्न देशों से टकराव भी मोल ले रहे हैं। व्यापार, पश्चिम एशिया के हालात से लेकर पर्यावरण जैसे मसलों पर उनका कठोर रवैया यही बताता है कि वह अमेरिकी हितों के आगे और किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वह कूटनीतिक तौर-तरीकों को भी दरकिनार करने में संकोच नहीं करते। जब वह ऐसा करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति कम, वहां के कारपोरेट जगत के संरक्षक ज्यादा दिखते हैं और यही आभास कराते हैं कि उन्हें दुनिया की समस्याओं की कहीं कोई परवाह नहीं। ट्रंप विभिन्न देशों पर दबाव डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने मोदी से मुलाकात के पहले इस आशय का ट्वीट किया कि भारत को अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करना होगा। उनके ऐसे ट्वीट यही बताते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी ही चलाना चाहते हैं। उनके इस रवैये के चलते ही अमेरिका के चीन से भी रिश्ते बिगड़े और रूस से भी। ओसाका में ट्रंप और मोदी की मुलाकात के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। इस दौरान भारत ने यह साफ कर दिया था कि वह अमेरिका से रिश्ते मजबूत करते हुए अन्य देशों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों की अनदेखी नहीं कर सकता और वह अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ही फैसले लेगा।

अवधेश राजपूत

अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत को पाकिस्तान और चीन के खतरे से निपटने के साथ ही निर्धनता और अशिक्षा जैसी समस्याओं से भी लड़ना है। इसमें उसे अमेरिका की मदद चाहिए। इसी कारण भारत यह चाहता है कि अमेरिका से रिश्ते मजबूत हों। ये मजबूत होने भी चाहिए, क्योंकि दोनों दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली लोकतंत्र हैं। ऐसे लोकतांत्रिक देशों को एक-दूसरे का स्वाभाविक मित्र होना चाहिए। अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत ने उसके उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला तब किया जब उसने भारत को तरजीही राष्ट्र वाली जीएसपी व्यवस्था से बाहर करने का फैसला किया। चूंकि अमेरिका इन दिनों चीन के साथ अपने व्यापार असंतुलन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए वह उसके प्रति तीखे तेवर अपनाए हुए है। इसके चलते तमाम अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं और भारत में अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रही हैं। अमेरिका इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर मान रहा है, लेकिन भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है।

भारत को अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलते समय यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी अमेरिकी कंपनियां ही भारत आएं जो मेक इन इंडिया में सहायक बनें और साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में ही अपने माल का उत्पादन करें और ऐसा करते समय तकनीक भी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही भारत को वह उच्च तकनीक भी चाहिए जो देश के तेज चहुंमुखी विकास में सहायक बन सके। फिलहाल इसमें भारत को बड़ी सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी कंपनियां तरह-तरह के आश्वासन तो देने में लगी हुई हैं, लेकिन वे वांछित तकनीक देने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। वे वही तकनीक भारत को देने को तत्पर हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिख रहा है। निःसंदेह आज आतंकवाद एक बड़ा खतरा है और भारत को चीन एवं पाकिस्तान से भी सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इन खतरों से निपटने की तैयारी करते हुए भारत को अमेरिका से केवल रक्षा-सुरक्षा संबंधी बड़े सौदे करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरी करते हुए यह भी देखना होगा कि देश रक्षा सामग्री के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बने? यह तभी संभव होगा जब विश्व की अग्रिम हथियार निर्माता कंपनियां भारत आकर अपनी तकनीक भी हस्तांतरित करें। भारत को इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के फेर में वैसी सामग्री खरीदने से बचे जो उसके बहुत अनुकूल न हों।

भारत को अमेरिका से न केवल अपनी जरूरत के हिसाब से रक्षा तकनीक चाहिए, बल्कि वह तकनीक भी चाहिए जो देश के स्वास्थ्य, शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर सके। इसी के साथ भारत को पर्यावरण अनुकूल ऐसी तकनीक भी चाहिए जो प्रदूषण संबंधी समस्याओं से निपटने में मददगार हो। चूंकि विदेशी कंपनियां अपना हित पहले देखती हैं इसीलिए वे भारत के विभिन्न नियम-कानूनों में तो ढील चाहती हैं, लेकिन भारत की सभी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। भारत की एक बड़ी प्राथमिकता गरीबी से लड़ने के साथ अपने आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास करना है। गरीबी दूर करने के साथ अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत को अच्छे-खासे विदेशी निवेश की आवश्यकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि अमेरिकी कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्साहित नहीं दिख रही हैं। शायद इसका एक कारण यह है कि ऐसे क्षेत्रों में निवेश बहुत लाभकारी नहीं होता। भारत को इस मुश्किल को आसान बनाने पर ध्यान देना होगा। अमेरिका को भी यह चाहिए कि वह भारतीय हितों की चिंता करते हुए ही अपने हितों की पूर्ति की अपेक्षा करे। वास्तव में ऐसा होने पर ही दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी।

response@jagran.com

जनसेवा के लिए नेताजी की नई विधा

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

अगर यह विकास दो-चार टांगें टूटना भी 'अफोर्ड' नहीं कर सकता तो सोचिए उसकी नींव कितनी खोखली है

लंदन से जैसे ही विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन की खबर विलायत से आई, देश के भीतर छुपे होनहार 'खिलाड़ी' छटपटा उठे। उन्हें अपने हुनर को आजमाने का अच्छा अवसर दिखाई दिया। हमारे यहां राजनीति का क्षेत्र कभी भी प्रतिभा-शून्य नहीं रहा। जब भी लगा कि देश 'गलत' दिशा में आगे बढ़ रहा है, राजनीति हमें 'सही' राह पर ले आती है। जनसेवक जी इस काम के लिए सबसे आगे आए। वह 'बल्लेबाजी' के लिए इतने आतुर हुए कि एक राजसेवक के पैरों को ही स्टंप समझकर उखाड़ने लगे। बुरा हो ऐसी व्यवस्था का जिसने ऐसी प्रतिभा को सम्मानित करने के बजाय हवालात में डाल दिया। यह तो अच्छा हुआ कि 'जनसेवा' करने के तुरंत बाद हवालात जाने से पहले वह हमसे बातचीत को तैयार हो गए। उस दुर्लभ मुलाकात में पहला सवाल हमने यही पूछा कि आपको ऐसी बल्लेबाजी की प्रेरणा कैसे मिली? सवाल सुनकर वह शून्य की ओर ताकते हुए बोले, 'दरअसल, हम बचपन से बल्लेबाज बनना चाहते थे। स्कूल टीम में हमने सिर्फ दो साथियों के सिर फोड़े, फिर भी चयन नहीं हुआ था। चयनकर्ता चाहते थे कि जब तक हम टांग तोड़ने की कला विकसित नहीं कर लेते, तब तक कामयाब खिलाड़ी न बन पाएंगे। तब हम मन मसोसकर रह गए थे। अब जनता ने ही हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया तो हम भला क्यों चूकते!'

'आपने 'बल्लेबाजी' से यह अद्भुत कारनामा कैसे किया?' हमने भी 'दूसरा' फेंकते हुए उन्हें चौंकाया।

इससे वह कतई नहीं चौंके। बड़ी सहजता से खेल गए। कहने लगे, 'हम हमेशा नए प्रयोग करने के हामी रहे हैं। गोली-बंदूक से मारने की परंपरा अब पुरानी हो चुकी है। हम इस तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। यहां तक कि 'जूतामार' कला भी आउटडेटेड हो चुकी है। पुरानी तरकीबों से न हनक बढ़ती है, न 'टीआरपी।' ले-देकर हमारे पास यही वकल्प बचा था। सामयिक होने के नाते भी 'बल्ला' हमारी प्राथमिकता में था। इसलिए नई तकनीक का सहारा लिया। कलाई के बेहतर प्रयोग के कारण 'बैटमार' एक उन्नत कला है। यह सबको ठीक से आती भी नहीं।' उनका यह जवाब सुनकर हमने 'यार्कर' डालने की कोशिश की-'पर कुछ लोगों का कहना है कि आपके इस तरह 'बल्लेबाजी' करने से विकास अवरुद्ध हो सकता है। उसके कदम रुक भी सकते हैं?'

जनसेवक जी एकदम से भावुक होते हुए बोले, 'अगर विकास दो-चार टांगें टूटना भी 'अफोर्ड' नहीं कर सकता तो खुद सोचिए, उसकी नींव कितनी खोखली है। हम ऐसा 'विकास' नहीं चाहते। किसी देश का इतिहास यूं ही नहीं बनता। वह प्रतिक्षण बलिदान मांगता है। इस बारे में हमारी कार्यप्रणाली एकदम स्पष्ट है। पहले आवेदन फिर निवेदन, इसके बाद दे-दनादन। पता नहीं क्यों विरोधियों को यह नहीं सुहा रहा है।' 'आप पर कानून हाथ में लेने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या यह बात सही है?'

वह हंसते हुए बोले, 'यह आरोप तो एकदम निराधार है। कानून को हाथ में लेने का सवाल ही नहीं है। हम इसे ससम्मान अपनी जेब में रखते हैं। और हां, कानून को अपने हाथ में रखने वाले आजकल खाली हाथ घूम रहे हैं। सबने देखा है कि हमारे हाथ में केवल 'बल्ला' था। हम तो सिर्फ 'आक्रामक बल्लेबाजी' कर रहे थे।' उनकी इस बालसुलभ मासूमियत देखकर हम भी अपनी 'औकात' भूल बैठे। उसी मासूमियत से पूछ बैठे, 'आपको इतना तो याद होगा कि 'बैटिंग' करते हुए आपने कितना 'स्कोर' बनाया था?' वह छूटते ही बोल पड़े-'हमें बल्ले के अलावा कुछ भी याद नहीं। हमारा 'स्कोर' तो जनता चुनावों में बताएगी। एक और पते की बात बताता हूं। किसी गरीब का दुख हमसे देखा नहीं जाता। उसी दुख को दूर करने की यह छोटी-सी कोशिश थी, बस। फिर मौका मिलने पर हम जनसेवा से पीछे नहीं हटेंगे।'

'अच्छा आखिरी बात। आपको हवालात जाने का कितना दुख है?' हमने छोटी बॉल डालकर उन्हें ललचाया। वह जैसे इसी इंतजार में थे। बॉल को सीमापार भेजते हुए बोले, 'लगता है आपकी भी हिंदी खराब है! अरे भाई, चोर और उचक्के 'हवालात' जाते हैं। जनसेवक हवालात नहीं, कारागार जाते हैं। कारागार तो हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम यहीं से चुनाव लड़कर इतिहास रचेंगे। अतीत से हम यही सबक ले रहे हैं, पर 'बिकाऊ-मीडिया' यह नहीं बताएगा। आप अपनी हिंदी दुरुस्त कीजिए। हम देश को दुरुस्त कर रहे हैं।'

ऐसा कहकर उन्होंने बल्ला उठा लिया। यह देख हमने भी अपनी 'गेंदबाजी' खत्म करने में ही भलाई समझी।

response@jagran.com

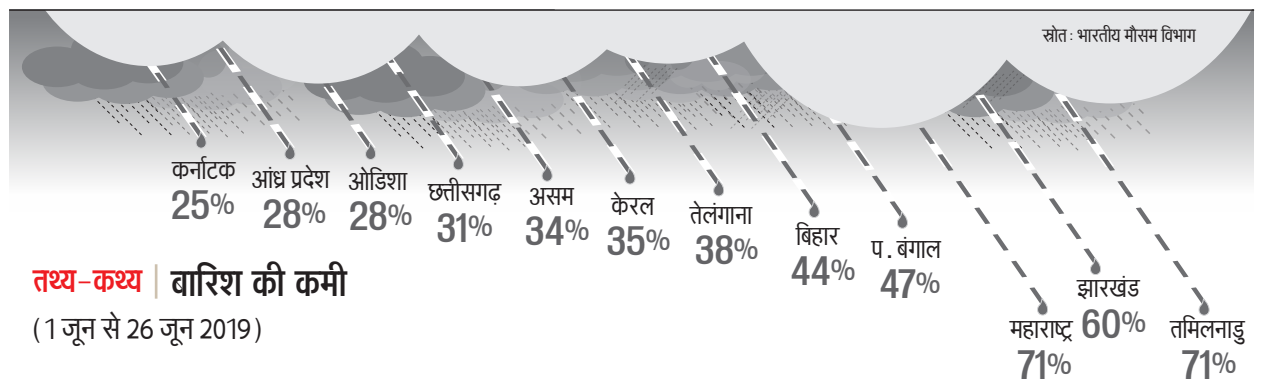

तथ्य-कथ्य | बारिश की कमी
(1 जून से 26 जून 2019)

ऊर्जा

सबल मन

मन की शक्ति का विघटन अंतर्द्वंद्व से होता है। संघर्ष, विरोधी वासनाओं या विचारधाराओं की विषमता से उत्पन्न होता है। विषमता से सजग रहें। अपने आदर्श इतने ऊंचे भी न बनाएं जिनका निर्वाह न हो सके। अपने आदर्शों और इच्छाओं में समता उत्पन्न कीजिए। समता से स्थायी मानसिक शांति मिलती है। मन को ऐसे विचारों से भरिए जो हितकर, शांतिकर व पुष्टिदायक हों अर्थात जिनसे आपको वास्तविक शक्ति व आत्मविश्वास मिले, आत्मश्रद्धा में वृद्धि करे। हम सबल हैं, प्रत्येक ओर से सतर्क व पुष्ट हैं-ऐसी विचारधारा से मन सबल होता है। मन को नए उत्तम विचारों से भरे रखिए। मस्तिष्क में जितने ही नवीन शांतिदायक विचार आएंगे, उतना ही मन सबल होगा। अनुपयोगी विचारों को त्याग दें। जीवन जीने का नियम यही है कि निरुपयोगी विचारों को त्याग कर मन में उपयोगी विचार धारण करें। उन्नति, प्रेम, विश्वास, उत्साह, विकास, प्रगति और शांति की भावनाओं का स्वागत करने से मन-मस्तिष्क प्रफुल्लित होता है। जीवन और शक्ति की वृद्धि होती है।

इसके उलट घोर निराशा से ग्रस्त व्यक्ति को आंतरिक संतुलन प्राप्त करने की दिशा में बिना देर किए जुट जाना चाहिए। चिंता से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसके कारणों को समझकर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन की अद्भुत शक्तियों का ह्रास अंतर्द्वंद्व से होता है। इसलिए इसे मानसिक जगत में स्थान न दीजिए। जब कभी चिंता सताए, तब उसका सामना बुद्धिमता से करें। जब चिंता सताए तो समझिए कि मनन की महती आवश्यकता हो गई है। बहुधा मनुष्य आचरण के विपरीत कार्य कर बैठता है। फलस्वरूप उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है। अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चाताप आवश्यक है। अपने मन में इसे स्थायी रूप से स्थान देने पर मन रोगी हो जाता है। वास्तव में आत्मग्लानि का अर्थ यही होना चाहिए कि भविष्य में उन गलतियों को न दोहराएं। आप पुण्य को, सत्य को, प्रेम को ग्रहण करने का प्रण करें, मन में शुभ कल्पनाएं रखें, यही निराशा से मुक्त होने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। चिंता का एक स्थायी कारण होता है। कुछ सामयिक कारण उस प्रधान कारण से मिल जाते हैं और मूल कारण को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए चिंता के बजाय चिंतन करें।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

टाइटन पर नासा का ड्रोन मिशन

मुकुल व्यास

शनि के इस चंद्रमा पर मौसम और सतह की प्रक्रियाओं से ऐसे हालात बनते हैं जो जीवन के लिए सहायक हो सकते हैं

अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी 'नासा' ने शनि के बर्फीले चंद्रमा टाइटन पर जीवन की संभावनाओं की पहचान के लिए ड्रैगनफ्लाइ नामक रोबोटिक क्वाडकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर ड्रोन भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन में बर्फीले चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र कर उसकी मिट्टी की संरचना को समझने की कोशिश की जाएगी। इस विशाल चंद्रमा को सौरमंडल में पृथ्वी जैसा पिंड माना जाता है। नासा के कैसिनी मिशन से पता चला कि वहां कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक माना जाता है।

नासा अपने न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 में ड्रैगनफ्लाइ मिशन को रवाना करेगा। इसके 2034 में टाइटन पर पहुंचने की उम्मीद है। शुरू में यह टाइटन के विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण करेगा जिनमें टीले और क्रेटर शामिल हैं। कैसिनी मिशन के दौरान संकेत मिले थे कि इन स्थानों पर कभी तरल जल मौजूद था। वहां जटिल कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के भी चिन्ह मिले थे। ड्रैगनफ्लाइ हेलीकॉप्टर इन सतही कार्बनिक पदार्थों के नमूनों को एकत्र करेगा। ड्रैगनफ्लाइ टाइटन के भूमध्य क्षेत्र में खास टीले पर उतरेगा। इसकी तुलना दक्षिणी अफ्रीका के नामीबियाई टीलों से की जाती है। यह रोबोटिक ड्रोन छोटी-छोटी उड़ानें भरेगा और विभिन्न स्थलों पर उतर कर वहां के नमूने एकत्र करेगा। इसकी लंबी उड़ान आठ किलोमीटर तक की होगी। यह यान करीब 175 किमी की उड़ान भरेगा। यह दूरी मंगल पर अभी तक भेजे गए समस्त रोवरों द्वारा मिलकर तय की गई दूरी से दोगुनी अधिक होगी।

नासा के एक अधिकारी थॉमस जुर्बुशेन का कहना है कि टाइटन सौरमंडल में सबसे अनोखा है और उसकी पड़ताल के लिए प्रस्तावित ड्रैगनफ्लाइ मिशन भी अपने आप में अनोखा है। जरा एक ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना कीजिए जो टाइटन के कार्बनिक रेतीले टीलों पर मीलों तक उड़ता रहेगा। टाइटन का आकार बुध ग्रह से बड़ा है और यह सौरमंडल में दूसरा बड़ा चंद्रमा है। शनि की परिक्रमा करते हुए सूरज से इसकी दूरी करीब 1.4 अरब किलोमीटर रहती है, जो पृथ्वी से दस गुना अधिक दूर है। सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण इसका तापमान माइनस 179 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 50 गुना अधिक है। पृथ्वी की भांति टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन आधारित है।

वहां मीथेन के बादल हैं और मीथेन की बारिश होती है। वायुमंडल में दूसरे कार्बनिक रसायन भी बनते हैं जो हल्की बर्फ की तरह नीचे गिरते रहते हैं। इस चंद्रमा के मौसम और उसकी सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं से ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो जीवन निर्माण में सहायक हो सकती हैं। न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत प्लूटो और काइपर बेल्ट के लिए न्यू होराइजन मिशन, बृहस्पति पर जूनो मिशन तथा बेनू क्षुद्रग्रह पर ओसिरिस- रेक्स मिशन भेजे जा चुके हैं। नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन के डायरेक्टर लोरी ग्लेज का कहना है कि न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम से हमें सौरमंडल को अधिक बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला है। हमें बृहस्पति के उग्र वायुमंडल, प्लूटो की बर्फीली सतह और काइपर बेल्ट के पिंडों के बारे में बहुत सी नई जानकारियां मिली हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

बंगले का मोह

चुनाव जीतने के बाद से राजधानी दिल्ली में आवास पाने की आस लगाए बैठे नए सांसदों को अब भी अपने आशियाने का इंतजार है। शपथ लेने के बाद भी कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जो अब तक सरकारी गेस्ट हाउस और होटलों में रहने को मजबूर है। यही कारण है कि इन दिनों नेताओं के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के घर आयोजित रात्रिभोज पर यह विषय चर्चा का मुद्दा बना रहा, जिसमें उन नेताओं की सराहना की गई जिन्होंने चुनाव हारते ही बिना देर किए घर खाली कर दिया, लेकिन इस चर्चा में उन नेताओं की चुगली भी की गई जो बंगला खाली न करने के अब तक बहाने बना रहे हैं। अब ऐसे में इस भोज पर पहुंचे एक हारे हुए नेता ने लौटते ही अपने निजी सहायक से सरकारी आवास खाली करने को कह दिया ताकि उनकी साफ छवि पर कोई दाग न आए। बावजूद इसके बंगले से दिल लगाए बैठे सहायक महोदय इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह वो किसी कोटे से मौजूदा मकान को साहब के नाम करवा सकें और उन्हें लुटियंस की दिल्ली से बेदखल न होना पड़े।

महाराजा की मूंछें

महाराजा की मूंछें नीची करने के लिए नेता और अफसर दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। जहां कुछ नेताओं ने निजी एयरलाइनों को फायदा पहुंचाने के लिए एयर इंडिया को जानबूझकर आगे बढ़ने से रोका। वहीं अफसरों ने इसकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनमें एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पर विदेशी एयरपोर्ट पर चोरी का आरोप लगा। बड़ी मुश्किल से एयर इंडिया वाले उन्हें विदेशी पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर भारत लाए। वरना ऑस्ट्रेलिया में उनकी गिरफ्तारी तय थी। इसके लिए इन्हें वहीं निलंबित कर आगे जांच व कार्रवाई का वादा किया गया। अब उनका भविष्य ऑस्ट्रेलिया के रुख पर निर्भर है। यदि वहां एफआइआर होती है तो भारत में भी जांच होगी और तब उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे इनके साथ हुआ यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सिंगापुर एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही वाकया हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक संबंधों की नजाकत के चलते वह बच गए थे। मगर इस बार भी वैसा होगा, कहना कठिन है।

पल में तोला, पल में माशा

राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सुबह-सुबह किए जाने वाले ट्वीट के निशाने पर इस बार भारतीय कूटनीति थी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट ने भारतीय विदेश मंत्रालय में भी खासा हड़कंप मच गया। दोनों नेताओं की जापान में मुलाकात होनी थी और तकरीबन दो दर्जन अधिकारी इसे सफल बनाने की तैयारियों में जुटे थे। पूरा दल इस बात से चिंतित था कि कहीं ट्रंप द्विपक्षीय वार्ता में तल्खी न दिखा दें। अमेरिकी पक्षकारों से भी बात की गई, लेकिन कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया। बहरहाल जब मोदी और ट्रंप मिले तो अमेरिकी राष्ट्रपति का मिजाज एकदम बदला हुआ था। उन्होंने एकदम बिंदास अंदाज में बात की। पूरी बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में हुई। स्वाभाविक है कि इससे सबसे ज्यादा राहत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को ही मिली होगी।

बिखरा हुआ विपक्ष

कहने को लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या 189 हो, लेकिन आपसी समन्वय के अभाव में यह कुनबा बुरी तरह बिखरा हुआ है। यही नहीं, नेतृत्व का अभाव भी विपक्षी बेंच पर साफ देखने को मिल रहा है। जहां अमित शाह की मौजूदगी के कारण सत्तापक्ष के अधिकांश सांसद सदन के भीतर उपस्थित दिखते हैं, वहीं विपक्षी बेंच अधिकांश खाली नजर आती हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल या फिर सदन की किसी दूसरी कार्यवाही के दौरान विपक्षी बेंचों पर वही सांसद दिखते हैं, जिन्हें बोलना होता है या फिर उनके बोलने की बारी आने वाली होती है। यही नहीं, नीतिगत मामलों में सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है। ले-देकर कांग्रेस को केवल तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सांसदों का ही साथ मिल पा रहा है। चंद वामपंथी व दूसरे दलों के छिटपुट सांसद सरकार के खिलाफ नीतिगत विरोध में कांग्रेस के साथ दिखते हैं। वाइएसआर कांग्रेस, टीआरएस और बीजद के सांसद अपना-अपना रुख अलग तय करते हैं जबकि भाजपा ही नहीं, पूरा राजग सदन के भीतर एकजुट नजर आता है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन ल